रजत प्रसाद

बनाम

सी बी आई

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 747)

अप्रैल 24, 2014

[पी. सदाशिवम, सीजेआई, रंजन गोगोई और एन. वी. रमना, जे. जे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 - धारा 12-दंड संहिता, 1860 - धारा 120 बी-स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने की साजिश जिसमें बदले में एक केंद्रीय मंत्री को रिश्वत देना शामिल है ताकि राज्य के विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर उसे बदनाम किया जा सके और इस तरह केंद्रीय मंत्री के प्रतिद्वंद्वी को राजनीतिक लाभ मिल सके। अपीलार्थी के विरुद्घ आपराधिक आरोप - इन्हें खारिज करना -उच्च न्यायालय द्वारा इनकार- औचित्य

निर्धारित किया गयाः चाहे पी. सी. अधिनियम की धारा 12 सपठित 120 बी आई.पी.सी. के अधीन अपराध किया गया हो या नहीं आदर्श रूप से, यह एक ऐसा मामला है जिसे मामले में साक्ष्य दर्ज होने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। -क्या ऑपरेशन वास्तव में एक ऐसी कवायद थी और ए-1 को रिश्वत देना महज एक दिखावा या दिखावा था या क्या रिश्वत देना खनन परियोजनाओं के संबंध में लाभ की उम्मीद के साथ था, ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल वही दे सकते हैं और इसमें पक्षों के साक्ष्य अभी आने बाकी हैं। ऐसे तथ्य किसी धारणा का विषय नहीं हो सकते। -वर्तमान मामले में स्टिंग और जनता के लिये इसका प्रसार किये जाने के बीच एक लंबा अंतराल (लगभग 12 दिन) क्यों था?यह भी एक पहलू है जिसके लिए जांच की

आवश्यकता होगी। ऑपरेशन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में अन्तर्वलित सम्भावनाएं हो सकती हैं कि वीडियोग्राऊी रिश्वत के प्राप्तकर्ता द्वारा आश्वासन दिए गए अनुग्रह के वितरण को दायित्व के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से पहले बाहर रखा जाना चाहिए - यह केवल साक्ष्य लेखबद्घ किये जाने के बाद ही हो सकता है- इसके अलावा, केवल इसलिए कि आरोपपत्र में यह कहा गया है कि आरोपियों ने स्टिंग ऑपरेशन राजनैतिक लाभ के लिये किया था यह अन्तिम निष्कर्ष निकाले जाने के लिये साक्ष्य के महत्व को कम नहीं करता। अपीलार्थीयों की कथित षडयन्त्र और भूमिका की सूक्ष्मता से पूर्ण जांच के लिये प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है - अपीलाथियों पर आरोपों के विरचन में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इन्कार पूणर्तः न्यायोचित है

आपराधिक विधी- आपराधिक कानून अपराध का पता लगाना-आपराधिक कृत्यों का प्रमाण-स्टिंग ऑपरेशन- यदि कानून प्रवर्तन के कानूनी तरीके के रूप में मान्यता प्राप्त है - भारत और कुछ विदेशी क्षेत्राधिकारों में स्थिति पर चर्चा की गई।

अपीलार्थी (ए-6 और ए-4) विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, दिल्ली की अदालत में एक मामले में अभियुक्त थे। अभियुक्तों के विरुद्घ आरोपों की गंभीरता यह थी कि अजीत जोगी का पुत्र अमित जोगी (ए-5), जो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री थे ने ए-3 से ए-6 के साथ मिलकर रिश्वत की रसीद दिखाने वाले एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने की साजिश रची थी ताकि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के चुनावों की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (ए-1) को बदनाम किया जा सके और इस प्रकार अजीत जोगी को राजनीतिक लाभ मिले जो कि केंद्रीय मंत्री के एक प्रतिद्वंद्वी है। 9 लाख रु मुद्रा नोटों की राशि ए-3 द्वारा ए-1 को सौंपी गई जिसे उन्होंने वहीं स्वीकार किया वही और ए-3 द्वारा प्रदान किये गये कपड़े धोने के थैले में उसे होटल से बाहर ले गए। पूरी घटना की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग व बातचीत का

आदान-प्रदान गुप्त रूप से किया गया था और बाद में इसे मीडिया में जारी किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने ए-1 के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत और ए-2 के विरुद्ध अधिनियम की धारा 7 सपठित आई.पी.सी. की धारा 120-बी के तहत अपराध करने का आरोप लगाया। जहां तक अन्य अपीलाथ्र्यों के साथ अभियुक्तों का प्रश्न् है अभियोजन के अनुसार उन्होंने धारा 12 के साथ आई.पी.सी. की धारा 120-बी के तहत अपराध कारित किया था।

अपीलार्थियों ने निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ धारा 12 भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के साथ धारा 120-बी के तहत आरोप तय करने के आदेश पर उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेप किया। उच्च् न्यायालय ने अपने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार करते हुए ट्रायल जज के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अभियुक्त-अपीलार्थियों के खिलाफ बनाए गए आपराधिक आरोपों को रद्द करने के लिए धारा 482 Cr.P.C के तहत वर्तमान अपीलों में चुनौती दी गई थी।

तत्काल अपीलों में, यह सवाल उठता है कि ऐसे ऑपरेशनों की स्थिति क्या होगी यदि इन्हें किसी राज्य एजेंसी द्वारा नहीं बल्कि एक निजी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है और दायित्व मुख्य अपराधी का नहीं है जो अपराध करने में फंसा है, बल्कि वह स्टिंग ऑपरेटर जिसने मुख्य अपराध और मुख्य अपराधी को फंसाते हुए अपने ही हाथ दाग लिए थे उसका है।

कुछ सहायक प्रश्न विचार के लिये उठे हैं

1. क्या ऐसे व्यक्ति यानी स्टिंग ऑपरेटर को उस अपराध के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए जो उस प्रक्रिया से अंतर्निहित और अविभाज्य है जिसके द्वारा किसी अन्य अपराध को स्थापित करने की मांग की जाती है?

2. क्या व्यापक जनहित के दावों के सामने पहले अपराध के किये जाने को मिटा दिया जाना और समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिसे स्टिंग ऑपरेटर सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक गंभीर अपराध के मुख्य अपराधी को बेनकाब करना चाहता है?

3. क्या स्टिंग ऑपरेटर द्वारा प्रारंभिक अपराध को अंजाम देना बिना किसी आपराधिक इरादे के और केवल "मुख्य अपराधी" द्वारा दूसरे अपराध को अंजाम देने और उसे जनता के सामने उजागर करने के उद्देश्य से किया गया समझा जा सकता है?

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया-

1.1. 'स्टिंग ऑपरेशन' शब्द "द स्टिंग" नामक एक लोकप्रिय फिल्म के शीर्षक से निकला है, जिसे वर्ष 1973 में प्रदर्शित किया गया था। यह फिल्म कुछ हद तक जटिल साजिश पर आधारित थी, जो दो व्यक्तियों द्वारा तीसरे को अपराध अपराध करने में प्रवृत्त धोखा देने के लिए रची गई थी। मूल रूप से एक भ्रामक ऑपरेशन होने के बावजूद, एक स्टिंग ऑपरेशन किसी अपराधी को पकड़ने के लिए बनाया गया, लेकिन यह कुछ सदाचार के और नैतिकता के प्रश्न उठाता है। पीड़ित, जो अन्यथा निर्दोष है, उसको परिस्थितियों की पूर्ण गोपनीयता और गोपनीयता के आश्वासन पर अपराध करने के लिए ललचाया जाता है, जिससे संभावित प्रश्न उठता है कि ऐसे पीड़ित को उस अपराध के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे उसने नहीं किया होता। एक और मुद्दा जो इस तरह के ऑपरेशन से उठता है वह यह तथ्य है कि अपराध को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए गए साधनों में स्वयं एक दोषी कृत्य शामिल होता है।

1.2 . अमेरिका और कुछ अन्य देशों के विपरीत, जहां स्टिंग ऑपरेशन को विधि की पालना में कानूनी पद्धति के रूप में मान्यता दी जाती है, हालांकि सीमित तरीके से जैसा कि आगे देखा जाएगा, भारत में ऐसी स्थिति नहीं है जो वर्तमान में उत्पन्न होने

वाले मुद्दों को जन्म देती है और मामले को अनोखा बनाती है। जनहित में किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन को आरके आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में इस न्यायालय की मंजूरी मिली है [1] हालांकि उक्त मामले में इस तरह की पद्धति की मंजूरी के अनुपात को समझना मुश्किल होगा। कानून प्रवर्तन का स्वीकार्य सिद्धांत सभी मामलों में मान्य है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में जहां मादक पदार्थों की तस्करी, राजनीतिक और न्यायिक भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, संपत्ति की चोरी, यातायात उल्लंघन आदि जैसे विभिन्न अपराधों में शामिल संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा स्टिंग ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है, आपराधिक न्यायशास्त्र इनके बीच अंतर करता है। "असावधान निर्दोष के लिए जाल और असावधान अपराधी के लिए जाल" उन स्थितियों को मंजूरी देना जहां सरकारी एजेंट "केवल अपराध करने के लिए अवसर या सुविधाएं प्रदान करते हैं" और ऐसी स्थितियाेंं की निंदा करना जहां अपराध कानून-प्रवर्तन अधिकारियों की "रचनात्मक गतिविधि का उत्पाद" है। बाद के प्रकार के मामलों में फँसाने के बचाव को संयुक्त राज्य अमेरिका में वैध बचाव के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि ठीक से स्थापित किया जाए तो ऐसा बचाव अभियोजन को हरा सकता है।

1.3 स्टिंग ऑपरेशन में फंसाने के बचाव को मान्यता देने वाला कुछ इसी तरह का न्यायशास्त्र कनाडा में विकसित हुआ है, जहां निर्दिष्ट शर्तों के तहत उपलब्ध बचाव, यदि स्थापित हो जाता है, तो आरोपी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही पर "रोक" लग सकती है, जिसका प्रभाव उक्त क्षेत्राधिकार में अभियोजन की समाप्ति होता है।

1.4 . यूनाइटेड किंगडम में एनट्रैपमेंट का बचाव एक ठोस बचाव नहीं है। हालांकि, न्यायिक व्यवस्था में बदलाव प्रतिक्रिया उभरती प्रतीत होती है।

1.5 इस प्रकार, उपरोक्त न्यायक्षेत्रों में स्वयं कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को अपराध का पता लगाने और आपराधिक कृत्यों के सबूत

के पूर्ण सिद्धांतों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे कार्यों का भारत में अभी तक प्रयोग और परीक्षण नहीं किया गया है और हमारी कानूनी प्रणाली द्वारा इसकी कानूनी स्वीकृति का अभी उत्तर दिया जाना बाकी है।

आर. के. आनंद बनाम पंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) 8 एससीसी 106 : 2009 (11) एस.सी.आर. 1026-संदर्भित।

शेरमन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 356 यू. एस. 359 (1958); सोरेल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 287 यू.एस.435(1932); आर बनाम रीगन [2002] 1 641 एस.सी.आर.297; आर बनाम मैक [1988] 2 एस.सी.आर.903; आर बनाम सांग (1980) एसी 402 और आर बनाम लूज़ली [2001] यूकेएचएल 53-संदर्भित।

2. इस अपील में जो सहायक प्रश्न विचार के लिये हैं उनका उत्तर, किसी भी आपराधिक मामले की तरह, उसके तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। कोई अपराध सिर्फ इसलिए मिटाया या ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके सार्वजनिक हित में किये जाने का दावा किया गया है। ऐसा कोई भी सिद्धांत हमारे आपराधिक विधिशास्त्र के लिए घृणित होगा। साथ ही, उस कार्य को करने के पीछे का आपराधिक आाशय, जिसके कारण अपराध हुआ माना जाता है, अपराध करने के आरोप वाले व्यक्ति के दायित्व का निर्णय करने से पहले स्थापित करना होगा। मेन्सरिया का सिद्धांत, हालांकि भारतीय आपराधिक न्यायप्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है, विभिन्न वैधानिक प्रावधानों में अभिव्यक्ति पाता है जिसके लिए अभियुक्त के इरादे या ज्ञान के प्रमाण की आवश्यकता होती है। इस तरह के सबूत को अदालत के समक्ष साक्ष्य और सामग्रियों द्वारा स्थापित आसपास के तथ्यों से इकट्ठा किया जाना चाहिए, न कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति की जांच की प्रक्रिया से जिस पर कि कानून विचार नहीं करता है। आईपीसी की धारा 107 द्वारा परिभाषित दुष्प्रेरण के अपराध या आईपीसी की धारा 120ए के तहत आपराधिक षडयन्त्र के अपराध के लिए, किसी भी अन्य

अपराध की तरह अपराधी की ओर से आपराधिक आशय की आवश्यकता होगी। दोनों अपराधों के लिए दोषी मनःस्थिति के अस्तित्व की आवश्यकता होगी जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों द्वारा स्थापित आसपास के तथ्यों से प्रमाण का विषय है। इसलिए, क्या पीसी अधिनियम की धारा 12 के तहत अपराध का कमीशन धारा 120 बी के साथ पढ़ा जाता है, आरोपी अपीलकर्ताओं के कृत्यों के कारण आईपीसी का अपराध हुआ था या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिसे आदशर् रुप से मामले में साक्ष्य दर्ज होने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। आरोपी अपीलकर्ताओं का कहना है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्टिंग ऑपरेशन एक पत्रकारिता अभ्यास था, इसमें भाग लेने वालों पर कोई आपराधिक इरादा नहीं लगाया जा सकता है। क्या ऑपरेशन वास्तव में एक ऐसी कवायद थी और ए-1 को रिश्वत देना महज एक दिखावा या दिखावा था या क्या रिश्वत देना खनन परियोजनाओं के संबंध में लाभ की उम्मीद के साथ था, ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल वही दे सकते हैं और इसमें पक्षों के साक्ष्य अभी आने बाकी हैं। ऐसे तथ्य किसी धारणा का विषय नहीं हो सकते। वर्तमान मामले में परिचालन और उसे जनता तक प्रसारित करने के बीच लंबा अंतराल (लगभग 12 दिन) क्यों था, यह मामले का एक और प्रासंगिक पहलू है जिसकी जांच की आवश्यकता होगी। वीडियोग्राफी के रूप में ऑपरेशन के दुरुपयोग की अंतर्निहित संभावनाएं, अर्थात्, रिश्वत के प्राप्तकर्ता द्वारा आश्वासन दिए गए एहसानों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उसका प्रतिधारण और उपयोग, दायित्व को जिम्मेदार ठहराने या बाहर करने से पहले बाहर रखा जाना चाहिए। ऐसा गवाहों की गवाही दर्ज होने के बाद ही हो सकता है. इसके अलावा, केवल इसलिए कि आरोप-पत्र में यह कहा गया है कि आरोपी ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऑपरेशन चलाया था, इससे आरोपी के आपराधिक इरादे के संबंध में उसके आधार पर वर्तमान मामले में स्वीकार्य निष्कर्ष निकालने के लिए उपरोक्त तथ्यों के सबूत के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से एक मुद्दा उठाया गया है कि अभियुक्तों की दोषिता के संबंध में कोई भी निष्कर्ष, यहां तक कि प्रथम दृष्टया भी, सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि न्यायालय की ऐसी कोई भी राय इसके लिए निषेध के रूप में कार्य करेगी। उद्यमशील और जागरूक पत्रकार और नागरिक उच्च पदों पर भ्रष्टाचार और अन्य अवैध कृत्यों को उजागर करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। इस मामले को अलग तरह से भी देखा जा सकता है. एक पत्रकार या कोई अन्य नागरिक जिसका रिश्वत की पेशकश के बदले कथित तौर पर मांगी गई मदद से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, उस पर धारा 12 के तहत उकसाने का अपराध करने या धारा 120 बी आईपीसी के तहत साजिश रचने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसलिए, ऐसी स्थितियों में कानून के उपरोक्त प्रावधानों की गैर-प्रयोज्यता, प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो सकती है। पत्रकारिता का उद्देश्य और सूचना एवं जागरूकता फैलाने में इसकी भूमिका और जिम्मेदारी धरी की धरी रह जाएगी। यह केवल उन मामलों में है जहां यह सवाल उचित रूप से उठता है कि क्या स्टिंग ऑपरेटर के पास उस लाभ में हिस्सेदारी थी जो कथित तौर पर रिश्वत के बदले में मांगी गई थी, इस मुद्दे को पूर्ण सुनवाई के दौरान निर्धारण की आवश्यकता होगी। उपरोक्त वर्णन निश्चित रूप से उन स्थितियों के बारे में संपूर्ण नहीं है जहां ऐसे और प्रश्न उठ सकते हैं जिनके लिए गहन जांच की आवश्यकता है। चूँकि ऐसी स्थितियाँ यदि अनंत नहीं हैं, असंख्य हैं,तो चित्रण के किसी भी प्रयास से बचना चाहिए।

4. अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि दायर आरोप पत्र में आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ सामग्री/आरोपों से उनके खिलाफ कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है, विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होगी और कार्यवाही के वर्तमान चरण में हमारे निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त तर्क को नकारने के लिए यह कहना पर्याप्त होगा कि कथित साजिश में ए-4 और ए-6 की सटीक भूमिका की पूरी जांच के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है। उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत उच्च न्यायालय का

दिनांक 30.05.2008 का आदेश, जिसमें अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरूद्ध लगाये गये आरोपों में हस्तक्षेप करने से इन्कार किया गया है, पूर्णतः उचित है।

संदर्भ कानून

2009(11)एससीआर 1026	संदर्भित किया गया है	पैरा 11
356 यूएस 359 (1958)	संदर्भित किया गया है	पैरा 11
287 यूएस 435 (1932)	संदर्भित किया गया है	पैरा 11
[2002] 1 एससीआर 297	संदर्भित किया गया है	पैरा 12
[1988] 2 एससीआर 903	संदर्भित किया गया है	पैरा 12
[1980] एसी 402	संदर्भित किया गया है	पैरा 13
[2001] यूकेएचएल 53	संदर्भित किया गया है	पैरा 13

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं 747/2010

दिल्ली उच्च न्यायालय के आपराधिक रिवीजन संख्या 2007 की 472 में दिनांकित 30.05.2008 के निर्णय और आदेश से।

साथ में 2010 की आपराधिक अपील सं. 748

पी.पी. मल्होत्रा, ए.एस.जी., यू.यू.ललित, पी.एस.नरसिम्हा, हारिस बीरन, मुश्ताक सलीम, राधा श्याम जेना, रोहित राव एन.,अनंगा भट्टाचार्य, रितेश के. चौधरी, एस. नागराजन, दिनेश कोठारी, यासिर रउफ, बी. कृष्ण प्रसाद पक्षकारों की ओर से

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

रंजन गोगोई, जे.

1. आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ तय किए गए आपराधिक आरोपों को रद्द करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से दिल्ली उच्च न्यायालय के इनकार को वर्तमान अपीलों में चुनौती दी गई है। विशेष रूप से, अपीलकर्ता, रजत प्रसाद और अरविंद विजय मोहन, जो कि विद्वान विशेष न्यायाधीश, सीबीआई दिल्ली की अदालत में सीसी केस नंबर 28, 2005 (इसके बाद ए-6 और ए-4 के रूप में संदर्भित) में क्रमशः छठे और चौथे आरोपी हैं ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद संक्षेप में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 12 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120-बी के तहत उनके खिलाफ आरोप तय करते हुए विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 24/25.04.2007 के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.05.2008 द्वारा विद्वान ट्रायल न्यायाधीश के उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अत: उपस्थितगण विशेष अनुमति द्वारा अपील की गई है।

2. जिन प्रासंगिक तथ्यों की गणना की आवश्यकता होगी उन्हें निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है।

16 नवंबर, 2003 को इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली संस्करण में "टेप पर पकड़ा गया: केंद्रीय मंत्री नकद लेते हुए कह रहे थे कि पैसा भगवान से कम नहीं है" शीर्षक के तहत एक समाचार छपा था, जिसमें दलीप सिंह जू देव (मृतक) के दृश्य दिखाए गए थे। पहला आरोपी) (ए-1), तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री, मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव की उपस्थिति में राहुल उर्फ भूपिंदर सिंह पटेल (तीसरे आरोपी) (ए-3) से अवैध परितोषण प्राप्त कर रहा था एक नटवर रतेरिया (दूसरा आरोपी) (ए-2)। उपरोक्त समाचार के प्रकाशन पर तुरंत केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली के एसीयू-द्वितीय द्वारा एक प्रारंभिक जांच दर्ज की गई थी और उक्त प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष पर

दिनांक 19.12.2013 को धारा 12 पीसी अधिनियम, 1988 सपठित धारा 120-बी आईपीसी के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए (ए-4 और ए-6) द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।

3. उपरोक्त एफआईआर को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक कार्यवाही में चुनौती दी गई थी जिसे विविध. केस नंबर 59/2004 सीआरएल के रूप में दर्ज और क्रमांकित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार जांच पर कोई अंतरिम रोक नहीं थी। जब जांच चल रही थी, सी.आर.एल. विविध. केस संख्या 59/2004 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। दिनांक 10.11.2004 के उक्त आदेश के विरुद्ध, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6336 वर्ष 2004 को चौथे अभियुक्त के साथ-साथ अन्य अभियुक्तों द्वारा इस न्यायालय के समक्ष स्थापित किया गया था। हालाँकि, जाँच पूरी होने पर 5.12.2005 को आरोप पत्र दायर किया गया था, उपरोक्त एसएलपी को निरर्थक होने के कारण दिनांक 23.11.2007 के आदेश द्वारा बंद कर दिया गया था।

4. सक्षम न्यायालय के समक्ष सीबीआई द्वारा दायर दिनांक 05.12.2005 के आरोप पत्र से, अभियुक्तों-अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों की गंभीरता यह प्रतीत होती है कि अमित जोगी (अभियुक्त संख्या 5) (ए -5) अजीत जोगी जो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री थे का पुत्र है। उसने केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (ए-1) द्वारा रिश्वत की प्राप्ति दिखाते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ए-3 से ए-6 के साथ मिलकर एक साजिश रची थी ताकि छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर उन्हें बदनाम किया जा सके और इस तरह श्री अजीत जोगी,जो केंद्रीय मंत्री के प्रतिद्वंद्वी थे, को राजनीतिक लाभ पहुंचाया जा सके। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रची गई साजिश के अनुसार, ए-5 अन्य सह-साजिशकर्ताओं के साथ शुरुआत में ए-5 के करीबी दोस्त मनीष राछोया (पीडब्लू-23) को कलकत्ता स्थित एक

खनन कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में लाया था, जो साजिशकर्ताओं में से एक के रूप था और उसका पर्यावरण और वन मंत्रालय में काम लंबित था। A-5 ने शेखर सिंह (PW-22) से उपरोक्त मनीष राछोया को A-1 से मिलवाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। उक्त बैठक होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में होनी थी और उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए ए-6 ने मनीष सरोगी के फर्जी नाम से होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में सुइट नंबर 151 बुक किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार मनीष का परिचय शेखर सिंह से हुआ था. हालाँकि, बाद में मनीष का रुख ठंडा हो गया और उसने ए-5 द्वारा रची गई योजना से खुद को अलग करने का फैसला किया। हालाँकि, A-5 के निर्देश पर, मनीष ने A-1 को सूचित किया था कि चूंकि सौदे में कुछ तकनीकी पैरामीटर थे, भविष्य में, उसका साथी राहुल (A-3) A-1 के साथ इस मामले पर चर्चा करेगा।

5. अभियोजन पक्ष का आगे का मामला, जैसा कि आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है, यह है कि इस स्तर पर राहुल उर्फ भूपिंदर सिंह पटेल (ए-3) को साजिश में शामिल किया गया था। वह कई दिनों तक होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली के सुइट नंबर 151 में रहा और उक्त होटल में कई मौकों पर ए-1 और ए-2 दोनों के साथ बैठकें कीं और सफलतापूर्वक उनसे दोस्ती की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 5.11.2003 को, राहुल (ए-3) ने होटल ताज महल, मान सिंह रोड, नई दिल्ली में कमरा नंबर 822 में प्रवेश किया था, जिसे रमन जड़ोजा के फर्जी नाम से बुक किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी दिन यानी 5.11.2003 को, ए-3 ने ए-1 और ए-2 से उक्त होटल के कमरे में उससे मिलने का अनुरोध किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ए-4 ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के डीलर मनोज होरा के माध्यम से ताज महल होटल, मान सिंह रोड, नई दिल्ली में उक्त सुइट के बैठक कक्ष में छिपे हुए वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरण की स्थापना की व्यवस्था की थी। 5.11.2003 की देर शाम ए-1 और ए-2 उक्त होटल पहुंचे और कमरा नंबर 822 गये. उनका मनोरंजन किया गया. ए-3 और अन्य दो

आरोपियों (ए-1 और ए-2) के बीच विभिन्न मामलों पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों में कुछ खनन परियोजनाओं से संबंधित मामले, जो मंत्रालय में लंबित थे, वे भी शामिल थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ए-1 और ए-2 दोनों ने ए-3 को आश्वासन दिया था कि लंबित प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने में आवश्यक सहायता की जाएगी। इसके बाद, 9 लाख रुपये की राशि के करेंसी नोट A-3 द्वारा A-1 को सौंप दिए गए, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और A-3 द्वारा दिए गए कपड़े धोने के बैग में इसे होटल से बाहर ले गए। पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ-साथ हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी गुप्त रूप से की गई और बाद में उसे मीडिया को जारी कर दिया गया। कार्यक्रम की वीडियो और ऑडियो कैसेट रिकॉर्डिंग को विश्लेषण के लिए भेजा गया था और उसकी रिपोर्ट एफएसएल, हैदराबाद से प्राप्त हुई थी। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने ए-1 के खिलाफ अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध करने और ए-2 के खिलाफ अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित आईपीसी की धारा 120-बी के तहत अपराध करने का आरोप लगाया था। जहां तक वर्तमान अभियुक्त-अपीलकर्ताओं सहित अन्य अभियुक्तों का संबंध है, अभियोजन पक्ष के अनुसार, उन्होंने आईपीसी की धारा 120-बी के साथ अधिनियम की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराध किए थे। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, दायर उपरोक्त आरोप पत्र के अनुसार, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी के साथ पीसी अधिनियम की धारा 12 के तहत आरोप तय किए थे।

6. हमने आपराधिक अपील संख्या 747/2010 और 748/2010 में अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील क्रमशः श्री उदय यू. ललित और श्री पीएस नरसिम्हा और प्रतिवादी के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पीपी मल्होत्रा को सुना है।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने जांच के दौरान ए-3 द्वारा उठाए गए दावे का उल्लेख करते हुए आरोप पत्र के प्रासंगिक भाग को हमारे सामने रखा है कि ए-1 को अवैध परितोषण के भुगतान का कार्य और उसी की गुप्त वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को उजागर करने की पत्रकारीय इच्छा से प्रेरित होकर की गई थी। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामला अत्यधिक सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठाता है, अर्थात्, अत्यधिक सार्वजनिक हित से प्रेरित एक स्टिंग ऑपरेशन की वैधता। विद्वान वकील के अनुसार, उक्त ऑपरेशन सरकारी सत्ता की सीटों पर संदिग्ध कार्यों को उजागर करने के लिए किया गया था। यदि ऐसा कोई आपराधिक कृत्य करने का इरादा किसी ऐसे नागरिक/पत्रकार को दिया जाता है जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो सार्वजनिक हित गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा। यह तर्क भी दिया गया है कि दायर आरोप पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि जांच से पता चला है कि पूरा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्रथम अपीलकर्ता को अपमानित करने के लिए किया गया था और ऑपरेशन के पीछे का उद्देश्य ए-5 के पिता,जो छत्तीसगढ़ राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, के पक्ष में राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था। यह तर्क दिया गया है कि यदि उपरोक्त स्टिंग ऑपरेशन का उद्देश्य था, तो निश्चित रूप से, अधिनियम की धारा 12 या 120-बी आईपीसी के तहत आरोपी-अपीलकर्ताओं के खिलाफ दूर-दूर तक कोई अपराध नहीं बनता है।

8. विद्वान वकीलों ने आईपीसी की धारा 120-ए में परिभाषित आपराधिक साजिश के अपराध की सामग्री को अदालत के सामने विस्तार से रखा है और तर्क दिया है कि (1) लक्ष्य को पूरा करने के लिए हेतुक की समानता होनी चाहिए; (2) एक योजना या योजना को पूरा करने का साधन शामिल है वह होना चाहिये; और (3) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता या सहमति जिसके तहत वे समझौते में सन्निहित साधनों द्वारा उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यह इंगित किया गया है कि आरोपपत्र में उल्लिखित जांच के परिणाम को

देखते हुए, जैसा कि पहले बताया गया था, अर्थात् ऑपरेशन का उद्देश्य ए-1 को अपमानित करना और ए-5 के पिता के पक्ष में राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था, साजिश, यदि कोई है, तो ए-1 को बदनाम करने के लिए है और आरोप पत्र में कथित किसी भी अपराध को करने के लिए नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आरोप पत्र को पढ़ने से पता चलता है कि A-3 से A-6 के खिलाफ कथित साजिश A-1 और A-2 के खिलाफ एक ही है, जबकि आरोप तय किया गया A-1 और ए-2 को उकसाने की साजिश के अपराध के लिए। ए-1 और ए-2 को फंसाने और बेनकाब करने के आरोपी के कथित इरादे और ए-1 द्वारा अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाने के आरोप के पीछे अंतर्निहित विरोधाभास पर प्रकाश डाला गया है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है, उनका आपराधिक आशय ए-1 और ए-2 की सहायता, सहायता या सुविधा प्रदान करना नहीं था, बल्कि ए-1 और ए-2 को उकसाने के आरोप को उजागर करना था- यह भी तर्क दिया गया है कि रिश्वत देने के पीछे कोई आपराधिक आशय नहीं था और कथित अपराध करने के लिए दुराशय का अभाव प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। आरोपी-अपीलकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने आरोप पत्र में उल्लिखित विशिष्ट आरोपों का हवाला देते हुए कहा है कि भले ही उक्त आरोपों को सही मान लिया जाए, लेकिन आरोपी-अपीलकर्ताओं में से किसी के खिलाफ कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है। इस संबंध में श्री नरसिम्हा ने बताया कि होटल के कमरे में स्थापित वीडियो उपकरण की व्यवस्था करने के आरोप के अलावा आरोपी ए-4 के खिलाफ कोई अन्य सामग्री नहीं है। उक्त तथ्य, अपने आप में, प्रथम दृष्टया आपराधिक साजिश के अपराध को आकर्षित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। जहां तक ए-6 का सवाल है, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ललित ने आग्रह किया है कि उक्त आरोपी की भूमिका केवल होटल ताज पैलेस में कमरे की बुकिंग के संबंध में है जहां मनीष राछोया (पीडब्लू-23) रुके हुए थे। हालाँकि, जैसा कि उपरोक्त मनीष राछोया

योजना से हट गया था और उसके बाद, कथित साजिश में कोई विशिष्ट भूमिका ए-6 को नहीं दी गई है, जहां तक ए-6 का संबंध है, अभियोजन पूरी तरह से अस्थिर है।

9. जवाब में, श्री पीपी मल्होत्रा, विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन में ए-1 को रिश्वत देना शामिल था जो उस समय में केंद्रीय मंत्री था और बदले में कुछ लाभ मांगे गए थे। हालाँकि घटना की वीडियोग्राफी करने के पीछे का उद्देश्य ए-1 को बदनाम करके राजनीतिक लाभ प्राप्त करना हो सकता है, लेकिन आईपीसी की धारा 107 के अर्थ में रिश्वत देना दुष्प्रेरण के समान है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को उजागर करने की अभियुक्त की पवित्र इच्छा के दावे के बावजूद उक्त आपराधिक कृत्य ख़त्म नहीं होगा। विद्वान अतिरिक्त. सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि मामले में साक्ष्य अभी दर्ज की जानी है। क्या उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में खनन परियोजनाओं में लाभ के लिए पैसे का आदान-प्रदान एक दिखावा था या अन्यथा वास्तविक था और किए गए ऑपरेशन के पीछे असली इरादे क्या थे, ये ऐसे मामले हैं जो मामले में साक्ष्य लेखबद्घ होने के बाद ही स्पष्ट होंगे। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि, उपरोक्त चरण तक पहुंचने और पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी आग्रह किया गया है कि आपराधिक आरोप को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अच्छी तरह से परिभाषित मापदंडों के भीतर किया जाना चाहिए, जिनमें से कोई भी वर्तमान मामले में मौजूद नहीं है।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि 'स्टिंग ऑपरेशन' शब्द "द स्टिंग" नामक एक लोकप्रिय फिल्म के शीर्षक से निकला है, जिसे वर्ष 1973 में प्रदर्शित किया गया था। यह फिल्म कुछ हद तक जटिल साजिश पर आधारित थी, जो दो व्यक्तियों द्वारा तीसरे को अपराध अपराध करने में प्रवृत्त धोखा देने के लिए रची गई थी। मूल रूप से एक भ्रामक ऑपरेशन होने के बावजूद, एक स्टिंग ऑपरेशन किसी अपराधी को पकड़ने के लिए बनाया गया, लेकिन यह कुछ सदाचार के और नैतिकता के प्रश्न उठाता है।

पीड़ित, जो अन्यथा निर्दोष है, उसको परिस्थितियों की पूर्ण गोपनीयता और गोपनीयता के आश्वासन पर अपराध करने के लिए ललचाया जाता है, जिससे संभावित प्रश्न उठता है कि ऐसे पीड़ित को उस अपराध के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे उसने नहीं किया होता। एक और मुद्दा जो इस तरह के ऑपरेशन से उठता है वह यह तथ्य है कि अपराध को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए गए साधनों में स्वयं एक दोषी कृत्य शामिल होता है।

11. अमेरिका और कुछ अन्य देशों के विपरीत, जहां स्टिंग ऑपरेशन को विधि की पालना में कानूनी पद्धति के रूप में मान्यता दी जाती है, हालांकि सीमित तरीके से जैसा कि आगे देखा जाएगा, भारत में ऐसी स्थिति नहीं है जो वर्तमान में उत्पन्न होने वाले मुद्दों को जन्म देती है और मामले को अनोखा बनाती है। जनहित में किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन को आरके आनंद बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में इस न्यायालय की मंजूरी मिली है [1] हालांकि उक्त मामले में इस तरह की पद्धति की मंजूरी के अनुपात को समझना मुश्किल होगा। कानून प्रवर्तन का स्वीकार्य सिद्धांत सभी मामलों में मान्य है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में जहां मादक पदार्थों की तस्करी, राजनीतिक और न्यायिक भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, संपत्ति की चोरी, यातायात उल्लंघन आदि जैसे विभिन्न अपराधों में शामिल संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा स्टिंग ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है, आपराधिक न्यायशास्त्र इनके बीच अंतर करता है। "असावधान निर्दोष के लिए जाल और असावधान अपराधी के लिए जाल" (शर्मन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य न्यायाधीश वॉरेन के अनुसार[2]) उन स्थितियों को मंजूरी देना जहां सरकारी एजेंट "केवल अपराध करने के लिए अवसर या सुविधाएं प्रदान करते हैं" और निंदा करना ऐसी स्थितियाँ जहां अपराध कानून-प्रवर्तन अधिकारियों की "रचनात्मक गतिविधि का उत्पाद" है (सोरेल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका[3])। बाद के प्रकार के मामलों में

फँसाने के बचाव को संयुक्त राज्य अमेरिका में वैध बचाव के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि ठीक से स्थापित किया जाए तो ऐसा बचाव अभियोजन को हरा सकता है।

12. स्टिंग ऑपरेशन में फंसाने के बचाव को मान्यता देने वाला कुछ इसी तरह का न्यायशास्त्र कनाडा में विकसित हुआ है, जहां निर्दिष्ट शर्तों के तहत उपलब्ध बचाव, यदि स्थापित हो जाता है, तो आरोपी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही पर "रोक" लग सकती है, जिसका प्रभाव उक्त क्षेत्राधिकार में अभियोजन की समाप्ति होता है। [आर बनाम रेगन[4] (पैरा 2)]

आर बनाम मैक [5] मामले में, कनाडाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह समझाया गया है कि फंसाना तब होता है जब (ए) अधिकारी किसी व्यक्ति को उचित संदेह पर कार्रवाई किए बिना अपराध करने का अवसर प्रदान करते हैं कि यह व्यक्ति पहले से ही आपराधिक गतिविधि या प्रामाणिक जांच के अनुसरण में शामिल है, और, (बी) इस तरह के उचित संदेह होने या प्रामाणिक जांच के दौरान कार्य करने के बावजूद, वे एक अवसर प्रदान करने से आगे चले जाते हैं और अपराध के किये जाने को प्रेरित करते हैं। निम्नलिखित कारक यह निर्धारित करते हैं कि क्या पुलिस ने अपराध करने का अवसर प्रदान करने से अधिक कुछ किया है।

(1) उस अपराध का प्रकार जिसकी जांच की जा रही है और पुलिस द्वारा उसके अपराध का पता लगाने के लिए अन्य तकनीकों की उपलब्धता

(2) क्या आरोपी की स्थिति में एक औसत व्यक्ति को, ताकत और कमजोरियों दोनों के साथ, अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ;

(3) आरोपी के अपराध करने के लिए सहमत होने से पहले पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या और दृढ़ता ;

(4) पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रलोभन का प्रकार जिसमें शामिल हैं: छल, धोखाधड़ी, चालाकी या इनाम;

(5) पुलिस कायर्वाही का समय, विशेष रूप से क्या पुलिस ने अपराध को उकसाया है या चल रही आपराधिक गतिविधि में शामिल हो गया है;

(6) क्या पुलिस आचरण में करुणा, सहानुभूति और मित्रता जैसी मानवीय विशेषताओं का शोषण शामिल है;

(7) क्या ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने किसी व्यक्ति की मानसिक विकलांगता या मादक द्रव्यों की लत जैसी किसी विशेष कमजोरी का फायदा उठाया है;

(8) आरोपी की तुलना में पुलिस की संलिप्तता के बीच आनुपातिकता, जिसमें आरोपी की तुलना में पुलिस द्वारा पहुंचाए गए नुकसान या जोखिम की डिग्री का आकलन और स्वयं पुलिस द्वारा किसी भी अवैध कार्य का कमीशन शामिल है;

(9) पुलिस या उनके एजेंटों द्वारा अभियुक्तों को दी गई किसी भी निहित या व्यक्त धमकी का अस्तित्व;

(10) क्या पुलिस का आचरण अन्य संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने के लिए निर्देशित है

13. यूनाइटेड किंगडम में फंसाने का बचाव कोई ठोस बचाव नहीं है जैसा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा आर बनाम सांग[6] में देखा गया है:-

> “पुलिस का आचरण जहां इसमें एक उत्तेजक एजेंट का उपयोग शामिल है, सजा को कम करने में विचार करने योग्य मामला हो सकता है; लेकिन आपराधिक न्याय की अंग्रेजी प्रणाली के तहत, यह न्यायाधीश की ओर से आरोपी को बरी करने या जूरी को ऐसा करने

का निर्देश देने के किसी भी विवेक को जन्म नहीं देता है, भले ही वह अपराध का दोषी हो।“

हालाँकि, न्यायिक प्रतिक्रिया में एक बदलाव उभरता हुआ प्रतीत होता है जिसे आर वी. लूज़ली[7] में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पाया कि:-

“फँसाने के आधार पर चलाया गया अभियोजन अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत राज्य की अभियोजन शाखा को इस तरह से व्यवहार करने की अनुमति नहीं देगी। (पैरा 16)

“फँसाना ऐसा मामला नहीं है जो केवल प्रतिवादी की दोषसिद्धि या दोषिता तक जाता है और इसलिए, दोषसिद्धि से अलग सज़ा दी जाती है। जिस परिस्थिति में यह किया गया था, उसमें राज्य की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित अपराध के लिए किसी भी तरह से अभियोजन चलाने के औचित्य पर फंसाया जाता है। (पैरा 17)

14. इस प्रकार, उपरोक्त न्यायक्षेत्रों में स्वयं कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन को अपराध का पता लगाने और आपराधिक कृत्यों के सबूत के पूर्ण सिद्धांतों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे कार्यों का भारत में अभी तक प्रयोग और परीक्षण नहीं किया गया है और हमारी कानूनी प्रणाली द्वारा इसकी कानूनी स्वीकृति का अभी उत्तर दिया जाना बाकी है। बहरहाल, वर्तमान मामले में यह सवाल उठता है कि ऐसे ऑपरेशनों की स्थिति क्या होगी यदि इन्हें किसी राज्य एजेंसी द्वारा नहीं बल्कि एक निजी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है और दायित्व मुख्य अपराधी का नहीं है जो अपराध करने में फंसा है, बल्कि वह स्टिंग

ऑपरेटर जिसने मुख्य अपराध और मुख्य अपराधी को फंसाते हुए अपने ही हाथ दाग लिए थे उसका है। क्या ऐसे व्यक्ति यानी स्टिंग ऑपरेटर को उस अपराध के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए जो उस प्रक्रिया से अंतर्निहित और अविभाज्य है जिसके द्वारा किसी अन्य अपराध को स्थापित करने की मांग की जाती है? क्या व्यापक जनहित के दावों के सामने पहले अपराध के किये जाने को मिटा दिया जाना और समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिसे स्टिंग ऑपरेटर सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक गंभीर अपराध के मुख्य अपराधी को बेनकाब करना चाहता है? क्या स्टिंग ऑपरेटर द्वारा प्रारंभिक अपराध को अंजाम देना बिना किसी आपराधिक इरादे के और केवल "मुख्य अपराधी" द्वारा दूसरे अपराध को अंजाम देने और उसे जनता के सामने उजागर करने के उद्देश्य से किया गया समझा जा सकता है? ये कुछ सहायक प्रश्न हैं जो वर्तमान अपीलों में हमारे उत्तर के लिए उठते हैं और वह भी अभियोजन की दहलीज पर यानी विचारण शुरू होने से पहले।

15. हमारे विचार में उपरोक्त का उत्तर, किसी भी आपराधिक मामले की तरह, उसके तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। कोई अपराध सिर्फ इसलिए मिटाया या ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके सार्वजनिक हित में किये जाने का दावा किया गया है। ऐसा कोई भी सिद्धांत हमारे आपराधिक विधिशास्त्र के लिए घृणित होगा। साथ ही, उस कार्य को करने के पीछे का आपराधिक आाशय, जिसके कारण अपराध हुआ माना जाता है, अपराध करने के आरोप वाले व्यक्ति के दायित्व का निर्णय करने से पहले स्थापित करना होगा। मेन्सरिया का सिद्धांत, हालांकि भारतीय आपराधिक न्यायप्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है, विभिन्न वैधानिक प्रावधानों में अभिव्यक्ति पाता है जिसके लिए अभियुक्त के इरादे या ज्ञान के प्रमाण की आवश्यकता होती है। इस तरह के सबूत को अदालत के समक्ष साक्ष्य और सामग्रियों द्वारा स्थापित आसपास के तथ्यों से इकट्ठा किया जाना चाहिए, न कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति की जांच की प्रक्रिया से जिस पर कि कानून विचार नहीं करता है। आईपीसी की धारा 107

द्वारा परिभाषित दुष्प्रेरण के अपराध या आईपीसी की धारा 120ए के तहत आपराधिक षडयन्त्र के अपराध के लिए, किसी भी अन्य अपराध की तरह अपराधी की ओर से आपराधिक आशय की आवश्यकता होगी। दोनों अपराधों के लिए दोषी मनःस्थिति के अस्तित्व की आवश्यकता होगी जो कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों द्वारा स्थापित आसपास के तथ्यों से प्रमाण का विषय है। इसलिए, क्या पीसी अधिनियम की धारा 12 के तहत अपराध का कमीशन धारा 120 बी के साथ पढ़ा जाता है, आरोपी अपीलकर्ताओं के कृत्यों के कारण आईपीसी का अपराध हुआ था या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिसे आदशर् रुप से मामले में साक्ष्य दर्ज होने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। आरोपी अपीलकर्ताओं का कहना है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्टिंग ऑपरेशन एक पत्रकारिता अभ्यास था, इसमें भाग लेने वालों पर कोई आपराधिक इरादा नहीं लगाया जा सकता है। क्या ऑपरेशन वास्तव में एक ऐसी कवायद थी और ए-1 को रिश्वत देना महज एक दिखावा या दिखावा था या क्या रिश्वत देना खनन परियोजनाओं के संबंध में लाभ की उम्मीद के साथ था, ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल वही दे सकते हैं और इसमें पक्षों के साक्ष्य अभी आने बाकी हैं। ऐसे तथ्य किसी धारणा का विषय नहीं हो सकते। वर्तमान मामले में परिचालन और उसे जनता तक प्रसारित करने के बीच लंबा अंतराल (लगभग 12 दिन) क्यों था, यह मामले का एक और प्रासंगिक पहलू है जिसकी जांच की आवश्यकता होगी। वीडियोग्राफी के रूप में ऑपरेशन के दुरुपयोग की अंतर्निहित संभावनाएं, अर्थात्, रिश्वत के प्राप्तकर्ता द्वारा आश्वासन दिए गए एहसानों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए उसका प्रतिधारण और उपयोग, दायित्व को जिम्मेदार ठहराने या बाहर करने से पहले बाहर रखा जाना चाहिए। ऐसा गवाहों की गवाही दर्ज होने के बाद ही हो सकता है. इसके अलावा, केवल इसलिए कि आरोप-पत्र में यह कहा गया है कि आरोपी ने राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ऑपरेशन चलाया था, इससे आरोपी के आपराधिक इरादे के संबंध में

उसके आधार पर वर्तमान मामले में स्वीकार्य निष्कर्ष निकालने के लिए उपरोक्त तथ्यों के सबूत के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है।

16. अपीलकर्ताओं की ओर से एक मुद्दा उठाया गया है कि अभियुक्तों की दोषिता के संबंध में कोई भी निष्कर्ष, यहां तक कि प्रथम दृष्टया भी, सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि न्यायालय की ऐसी कोई भी राय इसके लिए निषेध के रूप में कार्य करेगी। उद्यमशील और जागरूक पत्रकार और नागरिक उच्च पदों पर भ्रष्टाचार और अन्य अवैध कृत्यों को उजागर करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। इस मामले को अलग तरह से भी देखा जा सकता है. एक पत्रकार या कोई अन्य नागरिक जिसका रिश्वत की पेशकश के बदले कथित तौर पर मांगी गई मदद से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है, उस पर धारा 12 के तहत उकसाने का अपराध करने या धारा 120 बी आईपीसी के तहत साजिश रचने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसलिए, ऐसी स्थितियों में कानून के उपरोक्त प्रावधानों की गैर-प्रयोज्यता, प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो सकती है। पत्रकारिता का उद्देश्य और सूचना एवं जागरूकता फैलाने में इसकी भूमिका और जिम्मेदारी धरी की धरी रह जाएगी। यह केवल उन मामलों में है जहां यह सवाल उचित रूप से उठता है कि क्या स्टिंग ऑपरेटर के पास उस लाभ में हिस्सेदारी थी जो कथित तौर पर रिश्वत के बदले में मांगी गई थी, इस मुद्दे को पूर्ण सुनवाई के दौरान निर्धारण की आवश्यकता होगी। उपरोक्त वर्णन निश्चित रूप से उन स्थितियों के बारे में संपूर्ण नहीं है जहां ऐसे और प्रश्न उठ सकते हैं जिनके लिए गहन जांच की आवश्यकता है। चूँकि ऐसी स्थितियाँ यदि अनंत नहीं हैं, असंख्य हैं,तो चित्रण के किसी भी प्रयास से बचना चाहिए।

17. अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि दायर आरोप पत्र में आरोपी अपीलकर्ताओं के खिलाफ सामग्री/आरोपों से उनके खिलाफ कोई आपराधिक अपराध नहीं बनता है, विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होगी और कार्यवाही के वर्तमान चरण में हमारे

निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त तर्क को नकारने के लिए यह कहना पर्याप्त होगा कि कथित साजिश में ए-4 और ए-6 की सटीक भूमिका की पूरी जांच के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है।

18. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत उच्च न्यायालय का दिनांक 30.05.2008 का आदेश, जिसमें अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के विरूद्ध लगाये गये आरोपों में हस्तक्षेप करने से इन्कार किया गया है, पूर्णतः उचित है। तदनुसार, हम वर्तमान अपीलों को खारिज करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.05.2008 के आदेश की पुष्टि करते हैं।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीरज कुमार भारद्वाज (आरजेएस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और प्रामाणिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।